



















# कैसा सुशासन: मृत शिक्षकों का वेतन आहरण करने वाले दोषी प्राचार्य सुशासन की सरकार में डीईओ नियुक्त

खैरगढ़-छुईखदान-गंडई के डीईओ बनाए गए हैं प्राचार्य लालजी द्विवेदी, इनके खिलाफ कांग्रेस शासन में आर्थिक अनियमितता पर हुई थी कार्रवाई

पायनियर संबद्धता ▲ राजनांदगांव

www.dailypioneer.com

भाजपा की जीरो टॉलरेंस सरकार में शिक्षा विभाग में भाष्याचार के दोषियों और आरोपियों को उपकृत किया जा रहा है। इस आदेश में मृत शिक्षकों का वेतन आहरण किए जाने के दोषी प्राचार्यों को भी खैरगढ़-छुईखदान-गंडई जिले का डीईओ बना दिया गया है। यहीं नहीं मापदंडों के विपरिणीन नियुक्ति को लेकर भी बखेड़ा खड़ा हो रहा है। बुधवार की देर रात जिला शिक्षा अधिकारियों की हड्डी नियुक्ति के आदेश में भी शिक्षा विभाग में चल रही गड़बड़ीयों और उद्योग को सहाय पता दिया है। शिक्षा मंत्री बुजमान अग्रवाल के विभाग में अंदेखारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से भी ज्यादा गहरा कुच्छी है। 15 मार्च की जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश में विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राचार्यों को डीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में बखेड़ा खड़ा हो गया है। इन नियुक्तियों को समाचार प्रशासन विभाग के आदेश के प्रतिकूल भी बताया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को आदेश में विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राचार्यों को डीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में बखेड़ा खड़ा हो गया है। इन नियुक्तियों को समाचार प्रशासन विभाग के आदेश के प्रतिकूल भी बताया जा रहा है। यहीं नहीं चुनौती देने की तैयारी है। जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की इस सूची में खैरगढ़-छुईखदान-गंडई के डीईओ बनाए गए प्राचार्य लालजी द्विवेदी को लेकर भी सरकार कठोरे में खड़ी हो सकती है। यह काफी विवादास्पद पेसिंग बुजमान जीरो जा रही है। शिक्षाकीय कार्य उच्चरत माध्यमिक विद्यालय खैरगढ़ के प्राचार्य लालजी द्विवेदी को विभाग में वियुक्ति किया जाए तो यहीं नहीं चुनौती देने की तैयारी है। जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की इस सूची में खैरगढ़-छुईखदान-गंडई के डीईओ बनाए गए एवं प्राचार्य लालजी द्विवेदी को विभाग में अधिकारी बनाए गए हैं। यहीं नहीं इसी दीर्घा उद्देश्य एक शिक्षक को गलत तरीके से महांई भत्ता का एरियर भुजान भी किया था। डीईओ नियुक्त किए गए लालजी द्विवेदी को लेकर भी आर्थिक अपराधों के दोषी रहे हैं। नवंबर 2022 में उनके खिलाफ यह मामले सामने आए थे। तत्कालीन राजनांदगांव डीईओ एवं अग्रवाल सोम ने उहाँ नियुक्त करते हुए शिक्षायतों की जांच कराई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। इस खबर पर प्रतिक्रिया के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री बुजमान अग्रवाल से भी बातचीत का प्रयास किया गया लेकिन वे कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते उपलब्ध नहीं हो सके।

## हाईटे से शराब दुकान हटाने की तैयारी, चिरवली में खुलेगी

### चिखली में अंग्रेजी दुकान के लिए जगह तलाश रहा आबकारी

पायनियर संबद्धता ▲ राजनांदगांव

www.dailypioneer.com

वार्ड नं. 22 रेवाडी स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को आबकारी विभाग वार्ड नं. 06 चिखली स्थानान्तरित करने की तैयारी में थी। इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आबकारी ने निवादा निकालकर इस वार्ड में आपत्ति रहित स्थल में शराब दुकान के स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए रेवाडी के नाप्रक्रियक अंग्रेजी शराब दुकान का नियुक्ति भी दोषी रहे हैं। यहीं नहीं इसी दीर्घा उद्देश्य एक शिक्षक को गलत तरीके से महांई भत्ता का एरियर भुजान भी किया था। डीईओ नियुक्त किए गए लालजी द्विवेदी को लेकर भी आर्थिक अपराधों के दोषी रहे हैं। नवंबर 2022 में उनके खिलाफ यह मामले सामने आए थे। तत्कालीन राजनांदगांव डीईओ एवं अग्रवाल सोम ने उहाँ नियुक्त करते हुए शिक्षायतों की जांच कराई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। इस खबर पर प्रतिक्रिया के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री बुजमान अग्रवाल से भी बातचीत का प्रयास किया गया लेकिन वे कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते उपलब्ध नहीं हो सके।



भी धोणां की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के तीन माह की अवधि पूर्ण हो गई है और 90 दिन में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने 21 कैम्प प्रारंभ किए हैं, जो सुविधा केन्द्र भी हैं। इन सेवानीरी क्षेत्रों में आपका अच्छा गांव योजना के अंतर्गत पेयजल, सड़क, शिक्षा, राशन, आधार कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रारंभ होगी। प्रधानमंत्री ने 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि रेलवे सेक्टर में दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बनोपज एवं खनियों के लिए सार्वजनिक कार्य को नियुक्ति भी देनी है। उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की सहायता के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

का नियन्य भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि चरण पादुका योजना के तहत वनवासियों को चरण पादुका दी जाएगी, ताकि पैरों में काटे न गड़ा। उन्होंने कहा कि तेंपूता संग्राहकों के बच्चों के लिए आर्यवृत्ति एवं बीमा की व्यवस्था की जाएगी। सरकार उड़ानमंदों के खाते में आपकी अंग्रेजी उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

और तीन माह में 21 कैम्प प्रारंभ किए हैं, जो सुविधा केन्द्र भी हैं। इन सेवानीरी क्षेत्रों में आपका अच्छा गांव योजना के अंतर्गत पेयजल, सड़क, शिक्षा, राशन, आधार कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रारंभ होगी। प्रधानमंत्री ने 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि रेलवे सेक्टर में दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बनोपज एवं खनियों के लिए सार्वजनिक कार्य को नियुक्ति भी देनी है। उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों के लिए सार्वजनिक कार्य को नियुक्ति भी देनी है। उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार जरूरतमंदों को उड़ान योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का कार्य एवं खनियों के लिए संग्रहण दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की जरूरत है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये कार्यों की व्यव



